61वां तिब्बती राष्ट्रीय क्रान्ति दिवस के अवसर पर निर्वासित तिब्बती संसद का बयान।

सन् 1949 के प्रारम्भ में चीनी जनवादी गणराज्य के सेना तिब्बत में बलपूर्वक प्रवेश के साथ ही साम्यवादी चीन सरकार तिब्बतीयों पर छल कपट और धोखा इत्यादि प्रपंचों के सहारे महान देश तिब्बत पर जबरन कब्जा करने और परम पावन दलाई लामा जी के जीवन पर संकट लाने जैसे कार्य करते रहे। इस सुनियोजित षडयंत्र का वास्तविक चेहरा सामने आने पर जनसामान्य तिब्बतीयों में असहनशीलता का भाव स्वतः उत्पन्न हुआ। इस कारण 10.3.1959 के दिन तीनों प्रान्त के तिब्बतीयों ने एक साथ राजधानी ल्हसा में अहिंसात्मक जनांदोलन प्रारम्भ किया। आज उस अंदोलन को 61वां बरस हो रहा है। उस अंदोलन के दिन से ही हर साल सभी तिब्बती एकत्रित होकर उस दिन का स्मरण करते हैं। यह दिन तिब्बत के इतिहास के पन्नों में अतिमहत्वपूर्ण दिन के रूप में अंकित हो चुका है। इस दिन केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन देश के लिए बलिदान देने वाले वीर पुरुषो एवं वीर महलाओं के शाहिदी दिवस के रूप में भी याद करते हैं। सबसे पहले अपने देश के लिए अपना प्रिय शरीर तक सबकुछ न्योछावर करने वाले वीर पुरुषों एवं महिलाओं के साहस और पराक्रम को नमन करते हैं। इस समय भी चीन के दमनकारी नीति के तहत अनेक प्रकार के यातनाएं झेल रहे भुक्तभोगीयों के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं। और साथ ही त्रिरत्न से प्रार्थना करते हैं कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतीयों की हर कष्टों एवं पीड़ाओं से मुक्ति मिले जिससे आजादी की जिन्दगी जी सके।

चीन सरकार द्वारा तिब्बत पर बलपूर्वक आक्रमण करके अभी 70 साल से ज्यादा हो रहा है, इस अन्तराल में करोड़ से ज्यादा तिब्बतीयों के जान को नुकसान पहुँचाया गया। हज़ारों मठ सहित तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ, लुटा गया और छीना झपटी की गयी। हम तिब्बतीयों की पहचान हमारा धर्म, संस्कृति और भाषा को जड़ से उखाड़ने की क्रूर नीति अपनाई गई, यहाँ तक कि तिब्बत देश का असल मालिक तिब्बतीयों के मौलिक अधिकारों को छीनकर दमनकारी नीति के तहत नरक से भी बदतर हालात कर दिया गया। इससे भी बड़ी और गंभीर बात यह है कि चीन सरकार सुनियोजित नीति के तहत सम्पूर्ण तिब्बत को चीनी रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

चीन सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ तिब्बती अंदोलनरत है। 2008 को तिब्बत के हर क्षेत्र विशेषकर राजधानी ल्हसा और तिब्बत के तीनों प्रांतों में भारी मात्रा में जनांदोलन किया गया, जिसपर चीन के क्रूर सेना संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार करते हुए अहिंसात्मक अंदोलन को शस्त्रों सें दबाया गया। जिसमें सैकड़ों तिब्बतीयों को जना गवांना पड़ा। इसके अलावा साम्यवादी चीन की क्रूर दमन को झेल न पाने के कारण असहनीय परिस्थिति में सन् 2009 से 2019 के अन्त तक 154 तिब्बतीयों को आत्मदाह करना पड़ा है। उसके बावजुद चीनी नेताओं का तिब्बत समस्या हल करने पर विचार करने से इतर छल प्रपंच और झूठे वक्तव्य के सहारे चीनी नागरिकों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यथास्थिति को छुपाया जा रहा है। उसके ऊपर तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग होने का बार-बार गुमराह करने वाली बात बोली जाती है। जैसे युहान शहर में कोविद-19 विषाणु फैलने के समय, विषाणु से संक्रमित लोगों की वास्तविक संख्या और उससे मरने वालों की संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छूपाने की कुप्रथा चीनी नेताओं के स्वभाव में निहित है जो सबको पता है। तिब्बत कभी भी किसी देश के अधीन नहीं रहा बल्कि तिब्बत एक स्वतन्त्र देश रहा है। तिब्बत देश के इतिहास, भूभाग, नस्ल, भाषा, रीति रिवाज इत्यादि चीन तथा अन्य किसी भी देश से पूर्णतः भिन्न है, इससे यह साबित हो जाता है कि तिब्बत चीन का अंग नहीं है।

चीन का तिब्बत पर अपनाया हुआ सख्त नीति में अभी भी सकारात्मक परिवर्तन की कोई पहल नहीं है। 26.11.2019 के दिन अपरान्ह, तिब्बत के दो-मेद ङ्वा-मेरू-मयुल झील के निकट गाँव से 24 साल के योनतेन नामक तिब्बती ने तिब्बत पर चीन सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ अंदोलन कर आत्मदाह करने का मार्मिक खबर सामने आया है। येन केन प्रकारेण तिब्बतीयों की धरपकड़ कर हिरासत में लेकर यातना देना और गिरफ्तार कर सज़ा दिया जा रहा है। तिब्बतीयों के अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया है। हमारे धर्म की स्वतंत्रता को दरकिनार कर उसपर दमन हो रहा है। तिब्बतवासियों पर नस्लभेद की नीति अपनाया जाता है। विधि के खिलाफ जाने की आर में सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उदाहरणतः तिब्ब्ती द्वारा सामाजिक संचार के माध्यम से अपने मत प्रकट करने तथा परम पावन दलाई लामा जी के चित्र को भेजने जैसे कार्यों को अवैध घोषित कर बहुतों को जेल में डाला गया है। सबसे बड़े बौद्ध मठ याछेन-गर से 7000 से ज्यादा संख्या में भिक्षु एवं भिक्षुणियों को जबरन बाहर किया गया है। और सेरता-लरूङ्गर में भी पहले हज़ारों भिक्षु एवं भिक्षुणियों को बाहर कर, नये प्रवेश के लिए संख्या निर्धारित किया गया है। इस साल के प्रथम माह में चीन सरकार द्वारा 8 अध्याय 48 अनुच्छेद युक्त कानून लाया गया है जिसे "तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में एकता का मिसाल पत्र" नाम दिया है जिसको 1.5.2020 से लागु किया जा रहा है। इस कानून के अमल से हम तिब्बतीयों की आत्मा स्वरूप हमारी धर्म, संस्कृति, भाषा एवं सुप्रथाओं को चीन के संस्कृति में विलय होने का रास्ता बनाया गया है जो बेहद खतरनाक है। कुछ समय पहले निर्वासन से तिब्बत वापस लौटने वाले तिब्बतीयों को राजनीतिक तौर पर काले धब्बे के रूप में स्वीकारने की घोषणा की जा चूकी है। जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वासन में रह रहे

तिब्बती समाज के सामर्थ्य को कम करना और चीन सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाने की सोची समझी साजीश है। और चीन सरकार द्वारा तिब्बत तथा अन्य अल्पसंख्यक, धर्मोपदेशक तथा आस्थावान समाज पर विशेष तौर पर बनाए गये नए यन्त्र के माध्यम से पाबंदी लगा रहे हैं। खासकर 2020 में चीन के प्रत्येक स्थान पर आने जाने वाले लोगों पर नए यन्त्र से निगरानी रखकर शिकंजा कसने की तैयारी इत्यादि से स्पष्ट ज्ञात होता है। परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहा करते है कि इस एक्कीसवीं शताब्दी में हिंसात्मक कार्यवाही से भाईचारा और शांतिपूर्ण माहौल कायम नहीं हो सकता जो एक सच्चाई है। अगर चीन सरकार अपने मानव अधिकार की नीति और बदलते समय को ध्यान में रखकर अपनी अड़ियल रूख में सुधार लाते हैं तो चीनी समेत पुरी दुनिया में शांति एंव सुकून से जीने का माहौल बनाने में सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही यह भी कहना चाहते है कि चीन अपनी नीति में परिवर्तन लाकर अहिंसात्मक करूणामय उदारवाद की नीति की ओर आगे बढ़ें।

तिब्बतीयों की संघर्ष की पहचान शांति, अहिंसा और मध्यम मार्ग की नीति पर आधारित है, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन किए बिना चीन सरकार के साथ शांति वार्ता कर तिब्बत समस्या का हल निकालने का प्रयास केन्द्रीय तिब्ब्ती प्रशासन की तरफ से जो हो रहा है वह तिब्बत और चीन दोनों के लिए लाभदायक है। इसलिए अमेरिका, युरोप, भारत समेत दुनिया के कई देशों के सरकार, संसद, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। तिब्बती सहयोग मंच,अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा व्यक्ति विशेष इत्यादि अनेकों का प्रशंसा और सहयोग प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कि विदेश में बसे चीनी बुद्धिजीवी, लोकतंत्र कार्यकर्त्ता साथ ही चीन नागरिक अनेक निष्पक्ष बुद्धिजीवियों का प्रशंसा एवं समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत अनेक देशों द्वारा अपने-अपने संसद में तिब्बत विषय पर एक से ज्यादा अधिकारिक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तिब्बत में पारस्परिक आवागमन अधिनियम (Reciprocal Access to Tibet Act.) लागु किया। 28.1.2019 को तिब्बत नीति एवं समर्थन अधिनियम 2019 को अमेरिका के निचली सदन से प्रचंड बहुमत से पारित किया जा चूका है। 13.11.2019 को अमेरिका के निचली सदन के सदस्य श्री टेड योहो (Ted Yoho) श्री मिचेल मेक्कौल (Michael McCaul) श्री कराईस स्मिथ (Chris Smith) श्री जीम मेक्गोवर्न (Jim McGvorn) आदि ने तिब्बती जनता के लिए एक सार्थक स्वयात्त-शासन की अहमियता को रेखांकित करने के साथ ही परम पावन दलाई लामा जी के विश्व शांति, एकता,सभी मनुष्य के प्रति सम्भाव रखने की दृष्टि एवं प्रतिबद्धता को मान्यता देने हेतु सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया।

फिर से, अभी हाल ही में, 6 फरवरी 2020 को, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उपस्थिति में, वॉशिंगटन डीसी में 68 वें वार्षिक राष्ट्रीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें चीनी शासन में राजनैतिक कैदी रहे गोलोक जिग्मे को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया और इस प्रार्थना सभा में एक छोटी वृत्तचित्र दिखाई गई, जिसमें चीन सरकार द्वारा तिब्बत पर लगाए गए

प्रतिबंधों एवं धार्मिक स्वतंत्रता के विनाश पर प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर श्रीमती नेनसी पोलिसी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम यहाँ धार्मिक रुप से प्रताड़ित, गुमशुदा एवं नरसंहार किये गए करोड़ो लोगो के लिए अवाज और समर्थन देने हेतु एकत्रित हुए है मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमसब पेन्छेन लामा सहित चीन के जेल में बन्द सभी तिब्बती बन्दियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ।

2019 में 3 से 5 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए, तिब्बतीयों की तीसरी विशेष अधिवेषन निर्वासित तिब्बत के चार्टर के अनुच्छेद 59 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई, इसमें तिब्बतीयों के जन्म जन्मोत्तर के नाथ, परम पावन दलाई लामा जी के पूनर्जन्म सम्बन्धित अधिकार परम पावन दलाई लामा जी तथा उनके न्यास गादेन फोडंग के कार्यकारी पदाधिकारी मात्र के अलावा अन्य किसी भी सरकार, प्रशासन तथा व्यक्ति विशेष के पास अधिकार नही होने की बात कही गई। इससे पहले चीनी सरकार द्वारा घोषित किए गए तिब्बती लामाओं के पूनर्जन्म, विशेषकर 2007 में तिब्बती लामाओं के पूनर्जन्म से सम्बन्धित थोपे गए आदेश संख्या पाँच के आर में लामाओं के पुनर्जन्म खोज प्रक्रिया में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध के साथ निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 27 से 29 नवम्बर 2019, तीन दिवसीय 14वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में एकमत से परम पावन जी के पुनर्जन्म की याचना की गई। पुनर्जन्म से सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार परम पावन जी के अलावा अन्य किसी के पास नहीं होगा। साथ ही आठ सौ साल से अधिक के तिब्बती बौद्ध प्रणाली जो बौद्ध धर्म के विशुद्ध दर्शन से प्रेरित है, उस प्रक्रिया से पूनर्जन्म की खोज निश्चित होने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव की प्रभाव से 10 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता विभाग के पदाधिकारी श्री सेम-ब्रौनबेक (Sam Brownback) के धर्मशाला प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि, हम तिब्बतीयों के धर्म एवं संस्कृति, भाषा के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। तिब्बती संस्कृति मानव समाज के लिए किमती है। अमेरिका और तिब्बतीयों के सम्बन्ध साल दर साल प्रगाढ़ हो रहा है, हम तिब्बतीयों के साथ खड़े हैं। परम पावन जी के पुनर्जन्म तिब्बतीयों की अपनी विशेष परंपरागत व्यवस्था के अन्तर्गत होनी चाहिए, इसमें चीनी सरकार द्वारा हस्तक्षेप को अस्वीकार्य करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसपर अमेरिकी सरकार अपना समर्थन व्यक्त करता है। अमेरिका बिना हस्तक्षेप के तिब्बती अपने परम्परा का पालन करें उसका समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त इंगलैंड समेत कई अन्य देशों ने तिब्बत में पारस्परिक आवागमन (Reciprocal Access to Tibet) का प्रस्ताव संसद के पटल पर रखने के साथ ही उसपर चर्चा किया गया। इसके अलावा तिब्ब्त मसले को समर्थन देने वाले अनेक देशों ने अपने-अपने संसद में इस सम्बन्ध में विचार विमर्श स्थापित किया गया। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों द्वारा तिब्बत मसले को गम्भीरतापूर्वक लेने से यह स्पष्ट होता है कि पहले से ज्यादा समर्थन हासिल हो रहा है।

आपके इस समर्थन से तिब्बत और तिब्बतवासियों को अत्यधिक लाभ होता है अतः आप सबसे अनुरोध है कि समर्थन निरन्तर बनाए रखने का अनुरोध करते है।

2019 में 5 से 7 अक्टूबर तक निर्वासित तिब्बती संसद के तत्वावधान में, लात्वैय (Latvia) के शहर रिगा (Riga) में तिब्बत पर 7वां विश्व सांसद सम्मेलन का आयोजन किया गया,जिसमें विश्व के सांसद समेत सौ से अधिक गणमान्य सम्मिलित हुए। सम्मेलन में तिब्बत के पर्यावरण और विशेषकर तिब्बत मसले पर रिगा घोषणापत्र तथा रिगा कार्य योजना इत्यादि पर निर्णय लिया जा सका है। इसके बाद तिब्बत समर्थन समूहों का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में 3 से 5 नवंबर तक, तीन दिन के लिए परम पावन जी के निवास स्थान धर्मशाला में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में दुनिया के अलग-अलग 42 देशों से 180 से ज्यादा गणमान्यों ने भाग लेकर तिब्बत मसले पर वक्तव्य पेश किया। इस तरह के सम्मेलन से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

हमारे नई पीढ़ियों को यह जानना जरूरी है कि साम्यवादी चीन सरकार द्वारा छल कपट से 1959 को सम्पूर्ण तिब्बत पर जबरन कब्जा किये जाने से पहले तिब्बत पूर्णरूपेण एक स्वतंत्र देश था। चीन सरकार का अबतक अपने लोगों और दुनिया को गुमराह कर वास्तविकता से परे तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग बताकर झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच में सत्य का समर्थन करने वाले, चीन सरकार द्वारा जो झूठ और छल का नाटक किया जा रहा है उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता। तिब्बत का सत्य की संघर्ष को परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद, तिब्बत में रह रहे तिब्बतीयों का निःस्वार्थ और साहस आदि के बल पर निर्वासन में खासकर तिब्बती प्रशासन, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन तथा तिब्बती जनमानस पुरे शिद्दत के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों का हर प्रकार से निर्वाहन किया है और कर रहे हैं जिससे अभीतक तिब्बत मसला जीवित बचा है। तिब्बत समस्या का हल निकलने तक सभी तिब्बतीयों को तिब्बती प्रशासन के अन्तर्गत साथ देने के लिए आह्वान करता हूँ।

आजकल हमारे कुछएक लोग अपना अधिकतर महत्वपूर्ण समय मोबाईल और समाजिक मीडिया जैसे वट्सप, विचैट में व्यतीत कर रहा है जिससे कभी-कभी पंत विशेष तथा प्रांत विशेष पर हमारे अपनो में निराधार बहसबाजी से दरार पैदा हो रहा है। अतः हमें अपने किमती समय को अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपने देश के लिए देने का आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको आग्रह करता हूँ। इसके साथ ही सबको ज्ञात है कि तिब्बत देश हम तिब्ब्तवासियों का है, इस कारण इस समस्या का निराकरण की जिम्मेदारी भी प्रत्येक तिब्बतवासी को उठाना है इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम तिब्बतीयों की आत्मा स्वरूप हमारी धर्म,संस्कृति को बचाने के लिए अपनी भाषा और बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन करना अति आवश्यक जिसके बारे में एक अभिभावक के रूप में परम पावन दलाई लामा जी लगातर हमें याद दिलाते रहते हैं। चीन सरकार

हमारे धर्म, संस्कृति को जड़ से नष्ट करने के लिए हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, पर तिब्बत में रह रहे हमारे भाई बन्दु की निडरता,निःस्वार्थ भाव,साहस तथा परम पावन जी के आशीर्वाद और वयोवृद्धों की कृतज्ञता के बूते दुनिया के हर कोने से स्नेह और समर्थन करने वालों में बढ़ोतरी हो रहा है।

बीते दो महीने में चीन के वुहान शहर से शुरू हुए क्रोनावैरस (covid-19) नामक विषाणु तिब्बत समेत पुरे दुनिया में फैल रहा है, इसपर निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से अत्यन्त दुःख एवं संवेदना व्यक्त करते है। यह संक्रामक रोग आधी दुनिया तक फैल सकने की खतरा से आगाह किया चूका है अतः सभी को इस सम्बन्धित विशेष ध्यान देने हेतु आग्रह करता हूँ। जहाँ से विषाणु की उपज हुई है, उस वुहान शहर से तिब्बत में आवागमन मार्ग को पहले से बन्द न कर तिब्बत में रह रहे तिब्बतीयों को बिना एहतियात, बिना चिकित्सा उपचार के संक्रमण का खतरा बनाया गया है। तिब्बत के तहु जिले में इस विषाणु से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बड़ रहा है जो अत्यन्त खेद जनक है। तिब्बत अभी चीनी शासन के अन्तर्गत आता है अतः तिब्बतीयों को इस संक्रामक रोग से बचाने की पुरी जिम्मेदारी चीन सरकार की है। तिब्बतीयों की देख रेख भी एकसमान हो इसपर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हिदायत देने हेतु हम अनुरोध करते हैं। चीन सरकार इस संक्रामक रोग को यथाशीघ्र रोकथाम के लिए कदम ऊठाने पर काम करें।

तिब्बत की गम्भीर परिस्थिति को देखते हुए निर्वासित तिब्बती संसद भारत समेत विश्व के सरकारों एवं विभिन्न देशों के संसद, गणमान्य व्यक्तिविशेष तथा आम जनता से तिब्बत समस्या पर लगातार समर्थन प्राप्त कर रहे है। तिब्बत की सभ्यता अपने कठिनतम स्थिति में है, ऐसे समय में केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती समाज को हर प्रकार से सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्रों के मुख्या,संसद सदस्य,संगठन तथा व्यक्ति विशेष। खासकर भारत के केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा आम जनता को समस्त तिब्बत वासियों की ओर से हृदय से नमन एवं धन्यवाद करना चाहते हैं।

अन्त में परम पावन दलाई लामा जी की दीर्घायु की कामना के साथ उनकी हर इच्छा पूर्ण हो। और तिब्बत मसले का हल यथाशीघ्र निकले इसकी कामना करते हैं।

निर्वासित तिब्बती संसद

10.03.2020